Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

केन्द्रीय विकास योजनाएँ: मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अनेक जनकल्याण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा उम्मीद की जाती है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने में सक्षम होगा। यद्यपि आजादी के पश्चात् सरकार द्वारा अन्य योजनाएँ बनाई गईं उनका सफल क्रियान्वयन भी हुआ किन्तु बहुआयामी उद्देश्य प्राप्त नही की जा सके। देश की नागरिकों की आवश्यकता एवं बदलते परिवेश में नई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता समय-समय पर महसूस भी जाती रही है। नवीन सरकार की देश के विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें मध्यप्रदेश भी विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वनय में सुधार लाने एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने में मध्यप्रदेश आगे रहा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को कई पुरष्कार प्राप्त हो चुके हैं। आशा की जाती है कि वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ भविष्य में आने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा।

शोध प्रविधि: इस शोध के लिए दोनो प्रकार के समंको का सहारा लिया गया है। प्राथमिक समंक हितग्राही नागरिकों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की गई है, वहीं द्वितीयक समंक समय-समय पर प्रकासित समाचार पत्रों सरकारी रिर्पोटरों से संमंक जुटाये गये है।

विषय विश्लेषण: भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जिनका क्रियान्वयन सम्पूर्ण राष्ट्र में किया जा रहा है मध्यप्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी है प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी0एम0 आवास योजना, कृषि अधो संरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, पी0एम0 स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन आदि हैं। इस प्रकार एक दर्जन से अधिक योजनाएँ जिनका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्माण कर किया जा रहा है तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा समाज के हित में किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 1:मध्यप्रदेश की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

क्र.	योजना का नाम	संख्या	धनराशि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	575	8,20,000
2.	प्रधानमंत्री आवस योजना (ग्रामीण)	20	36,25,000
3.	जन जीवन मिशन	228	72,89,000
4.	अमृत सरोवर योजना	5839	.....
5.	मध्यप्रदेश ग्राम सड़क योजना	72965 कि.मी. निर्माण कार्य पूरा	.....

स्त्रोत:- रोजगार निर्माण, भोपाल 21.10.2024 से 27.10.2024 तक

उपरोक्त सरणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विकास योजनाओ की प्रगति उल्लेखनीय है तथा प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है तथा समाज का कायाकल्प तेजी से बदल रहा है। इसका कारण यह है कि केन्द्र व राज्य में एक ही दल की सरकार है, तथा प्रगतिशील बिचारधारा के क्रियान्वयन में विश्वास रखती है।

समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ– केन्द्रीय विकास योजनाएँ जनकल्याण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इनका क्रियान्वयन समग्र रूप से करने पर आम नागरिकों को भरपूर लाभ मिल सकता है किन्तु अनेक समस्याओं एवं कठिनाईयों के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापकता की कमी देखी गई है, कहीं सकफ क्रियान्वयन हुआ है तो कही आधा-अधूरा तथा कही पर बिल्कुल नही। इनका कारण पर्याप्त धन की कमी, सरकारी मशीनरी की उदासीनता, सतत् निरीक्षण एवं मूल्यांकन लापरवाह सरकारी मशीनरी पर ज्यादा अंकुश एवं लाल फीताशाही व शासकीय धन हड़पने की कोशिशें आदि रही है। जिस तत्परता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही की जाती है मैदानी क्षेत्र में उतनी दिखाई नहीं देती यही कारण है कि नई-नई योजनाएँ निर्मित की जा कर मैदान में उतारी जाती है।

सुझाव:

1. नगरिकों भी आवश्यकता के अनुसार सकफ सिद्ध होने वाली योजनाएँ ही तैयार की जाए।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. शासकीय मशीनरी कों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित व नियंत्रित की जानी चाहिए।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन की मनीटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. क्रियान्वयन में कमी होने पर तत्काल सुधार की कार्यवाही की जानी चाहिए।
6. योजनाओं के क्रियान्वयन में जन समुदाय के प्रतिनिधियों का भी

सहयोग लिया जाना चहिए।

7. लापरवाह निष्क्रिय व टाल-टूल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।
8. यदि योजनाओ में कही कमियॉ है तो उनमे सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष –जन कल्याण की दिशा में शासन द्वारा संचालित विकास योजनाएँ मध्यप्रदेश के विकास मे काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई है तथा आम नागरिकों को सहूलियतें एवं लाभ प्राप्त हुए है, अगर प्रस्तुत सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाय तो निश्चित ही मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा तथा विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा तथा विकसित राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रोजगार और निर्माण भोपाल दिनांक 21.10.2024 से 27.10.2024 तक
2. मध्यप्रदेश प्रगति प्रतिवेदन 2023-24

****